राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 12 | जौनपुर | सोमवार, 25 अगस्त 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

एसएसपी ने खुदकुशी करने वाले युवक के परिजनों से मुलाकात की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने 35 लाख रुपये ठगे जाने से परेशान होकर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले तलसारी गांव के युवक जितेंद्र सिंह नेगी के परिजनों से शुक्रवार को मुलाकात की और मामले में अभी तक की गयी कार्रवाई से अवगत कराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दोनों अधिकारियों ने नेगी के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन के उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी के फोन से दिवंगत युवक के पिता सतीश चंद्र से बातचीत की तथा अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। धामी ने उनसे कहा कि इस स्थिति में पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। बृहस्पतिवार तड़के चार बजे 32 वर्षीय नेगी ने अपने घर के पास अपनी कार में कथित रूप से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

दस साल से हो रही थी मतों की चोरी, निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए थी जांच : राज ठाकरे

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वह 2016 से ही 'वोट चोरी' की बात कर रहे हैं और जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा के अनुराग ठाकुर ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, तब निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच करने को कहा। राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा, ''जब विपक्ष के साथ–साथ सरकार के सदस्य भी संदेह जता रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग को उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन वह मामले को दबाना पसंद कर रहा है।''

जन समस्याओं के निराकरण में न हो हीलाहवाली, 200 लोगों की समस्याएं सुनीं : सीएम योगी

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद रविवार सुबह जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। ध्यान से उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण तत्परता और संवेदनशीलता से किया जाए। इसमें कोई हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। सीएम ने कहा कि ने जनता की हर समस्या के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक–एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सुनिश्चित किए जाएगा। सबकी बात सुनने के बाद प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण का निर्देश देने के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी सहायता की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के अस्पताल में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल जाकर किश्तवाड़ जिले में एक सुदूर गांव में अचानक आई बाढ़ में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिंह के साथ जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से यहां पहुंचने के बाद मंत्री सीधे जम्मू अस्पताल पहुंचे और वहां इलाज करा रहे 16 लोगों से मुलाकात की। गत 14 अगस्त को चिशोती गांव में बादल फटने से 65 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गये थे। तब से लापता 32 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने बताया कि सिंह को मचौल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले अंतिम गांव चिशोती भी जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण यह दौरा रद्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सिंह अब दिल्ली लौटने से पहले राजभवन जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम ने मंत्री को अपने इलाज के बारे में जानकारी दी।

गडकरी ने चार बाघ अभयारण्यों को जोड़ने वाले कॉरिडोर की घोषणा की

भोपाल, (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को मध्यप्रदेश के चार बाघ अभयारण्यों को जोड़ने वाले 5,500 करोड़ रुपये के चार लेन वाले कॉरिडोर और भोपाल व जबलपुर के बीच 15 हजार करोड़ रुपये के 'ग्रीनफील्ड हाईवे' की घोषणा की।गडकरी ने यहां सात किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद यह घोषणा की। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे, राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और राज्य के अन्य सांसदों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बाघ अभयारण्यों को जोड़ने वाले कॉरिडोर की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "टाइगर कॉरिडोर' की लागत 4,600 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 5,500 करोड़ रुपये हो गई है। यह कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच अभयारण्यों को जोड़ेगा।" उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार, मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा 785 बाघ हैं।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भोपाल और जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा 'ग्रीनफील्ड हाईवे' 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। गडकरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री राकेश सिंह से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से सुनिश्चित करने को कहा ताकि अगले अप्रैल या मई तक निर्माण कार्य शुरू हो सके।

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राज्य प्रभारी को कोई नाम नहीं सुझाया : सुक्खू

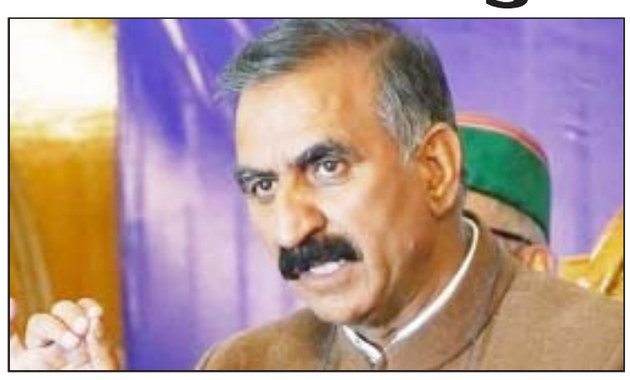

हिमाचल, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पर्वतीय राज्य के लिए पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कोई नाम नहीं सुझाया है। सुक्खू ने पाटिल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के चयन का फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। उन्होंने कहा कि वह केवल भविष्य के कार्यक्रमों और विधानसभा एवं जनता के बीच उठाए जाने वाले मुद्दों पर ही चर्चा कर सकते हैं। सुक्खू ने कहा, ''मेरे लिए सब बराबर हैं। पूरी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करती है और हम आलाकमान द्वारा की गई किसी भी नियुक्ति का समर्थन करेंगे।'' आपदा राहत पर विधानसभा में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जो कहती है और जो करती है, उसमें अंतर है। उन्होंने दावा किया, ''भाजपा ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर हम सहमत हो गए। हमने इस मुद्दे पर चार दिनों तक चर्चा की, लेकिन जब जवाब आया, तो भाजपा सदस्य सदन से बाहर चले गए।'' सुक्खू ने दावा किया, ''हमें अभी तक केंद्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। हम अपने संसाधनों से राहत प्रदान कर रहे हैं, घर निर्माण के लिए सात लाख रुपये, सामान के लिए 70,000 रुपये और मवेशियों के नुकसान के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।' ' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह शिमला में मौजूद केंद्रीय गृह सचिव से बात करेंगे और राज्य के लिए पर्याप्त विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे, जो लगातार बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान से जूझ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी और कहा कि इसकी शिक्षाएं मानवता को एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र पुस्तक है, जिन्हें समुदाय द्वारा जीवित गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शाश्वत शिक्षाएं दुनिया भर में जीवन को प्रकाशित करती रहती हैं और हमें करुणा, विनम्रता और सेवा के मूल्यों की याद दिलाती हैं।'' उन्होंने कहा कि ये शिक्षाएं मानवता को एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम सदैव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मार्ग पर चलें और एक बेहतर ग्रह बनाने का प्रयास करें।

कटनी खनन सम्मेलन में मध्यप्रदेश को मिले 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव : मुख्यमंत्री यादव

मुंबई, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य के कटनी जिले में आयोजित खनन सम्मेलन 2.0 के दौरान राज्य को आठ खनन कंपनियों से 56,414 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। उन्होंने शनिवार को सम्मेलन में कहा कि मध्यप्रदेश खनिज संसाधनों के मामले में कभी पीछे नहीं रहा और अब देश के खनन राज्य के रूप में खुद को विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से राज्य में उद्योग स्थापित करने का आग्रह किया और सरकार की ओर से उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। यादव ने कहा कि सम्मेलन देश भर के उद्योगपतियों की मध्यप्रदेश में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्ताव राज्य को खनन क्षेत्र में और प्रगति करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, प्रसंस्करण और विकास के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खनन क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई), ब्लॉकचेन और रिमोट सेंसिंग के उपयोग के लिए टेक्समिन आईएसएम, धनबाद के साथ एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने खनिज अन्वेषण अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईसर), भोपाल के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यादव ने कहा कि कटनी खनिज भंडारों से समृद्ध है और महत्वपूर्ण खनिजों की भी खोज हो रही है। पन्ना में हीरे के भंडार हैं और कटनी में सोने की भी संभावना है। राज्य ने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पारदर्शी नीतियों को लागू किया है। महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। अन्य राज्य मध्यप्रदेश की नीतियों से सीख रहे हैं और सरकार राज्य को देश में नंबर एक बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यापार सुगमता के लिए 29 प्रकार की अनुमतियों को घटाकर केवल 10 कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 27 अगस्त को उज्जैन में एक आध्यात्मिक सम्मेलन और 31 अगस्त को ग्वालियर में एक पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।

नाश्ता योजना का 20 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा : मुख्यमंत्री स्टालिन

तमिलनाडु , (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने रविवार को कहा कि 26 अगस्त को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार के बाद 20 लाख से अधिक स्कूली छात्र इस पहल से लाभान्वित होंगे, जिसका उद्देश्य बच्चों का पर्याप्त विकास सुनिश्चित करना है। अब इस योजना का विस्तार तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस योजना के विस्तार के दौरान बुधवार को मौजूद रहेंगे। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक 'पोस्ट' साझा कर कहा कि इस योजना से अब 20.59 लाख स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा, ''जस्टिस पार्टी के दिनों से लेकर द्रविड़ मॉडल सरकार तक हम बच्चों को भोजन प्रदान करते आए हैं और उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। यह सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि बच्चों के विकास के लिए एक मजबूत आधार है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाला सरकार का यह ''नवीनतम प्रयास'' जारी रहेगा और तमिलनाडु हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे एक पत्र में कहा कि तमिलनाडु ने कैसे इस तरह की पहल की थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत के. कामराज ने मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी। बाद में, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम जी रामचंद्रन (एमजीआर) ने इसे पौष्टिक भोजन योजना में बदला। स्टालिन ने कहा कि इसके वर्षों बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार ने छात्रों को दिए जाने वाले भोजन में अंडे को भी शामिल किया।

अररिया पहुंचकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी

अररिया, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया से अररिया पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वोट चोरी का प्रयास कर रही है। अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षणके माध्यम से गरीबों के वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग के समर्थन से वोट चुराने का एक संस्थागत तरीका बताया। गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार... सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण करने के बाद... अब चुनाव आयोग की मदद से के जरिए गरीबों के वोट चुराना चाहती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए चुनाव आयोग को श्चुनावी चूकश बताया। उन्होंने दावा किया कि यह कदम असंवैधानिक है और इसका मकसद बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले समाज के वंचित वर्गों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार में ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है और यह कदम पूरी तरह से संविधान–विरोधी है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों को करारा जवाब देगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और देश का पैसा कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो आपका वोट चोरी कर रहे हैं, आपका अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने बिहार की बेरोजगारी और गरीबी का जिक्र करते हुए कहा कि लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी श्वोटर अधिकार यात्राश बहुत सफल रही है क्योंकि बिहार की जनता श्वोट चोरीश की बात से सहमत है और उनसे जुड़ रही है। राहुल ने स्पष्ट किया कि उनका पूरा ध्यान चुनाव आयोग के इस रवैये को बदलने पर है और उन्होंने बिहार में चुनाव की चोरी नहीं होने देने का संकल्प लिया।

आंध्र प्रदेश की दंपति की फांसी की सजा बदली

कोलकाता, (एजेंसी)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक दंपति को, जिन पर एक साल के मासूम बच्चे की हत्या का दोष साबित हुआ था, मिली फांसी की सजा को घटाकर उम्रकैद कर दिया गया है। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला सबसे दुर्लभ मामलों में से दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास उपयुक्त होगा। कहा कि दोनों अभियुक्तों, शेख हसीना सुल्ताना और शेख वन्नूर शा, की उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें सुधरने का मौका दिया जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया कि उनकी उम्रकैद का मतलब होगा कम से कम 40 साल की जेल, जिसमें किसी तरह की छूट या रियायत नहीं मिलेगी।

संपादकीय

सांसदों से वसूली की जाए

लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गईं। यानी संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। यह संसद सत्र न भी होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राष्ट्रीय नुकसान नहीं होता। हम यह बहुत भारी मन से लिख रहे हैं, व्यथित महसूस कर रहे हैं। हालांकि यह कहना देशहित में नहीं है, क्योंकि संसद हमारा सर्वोच्च और गरिमामय लोकतांत्रिक मंदिर है। बार–बार यह महज एक कथन, आदर्श वाक्य लगता है, क्योंकि संसद एक अखाड़ा बन कर रह गई है। संसद सत्र के दौरान करीब 190 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। संसद की सार्थक कार्यवाही नहीं चल सकी। एक दिन की संसदीय कार्यवाही पर औसतन 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह राशि सांसदों की नहीं, बल्कि देश की करदाता जनता की है। हंगामे, शोर–शराबे और कार्यवाही के बार–बार स्थगन के लिए जनता पैसे क्यों दे? सदन चले अथवा स्थगित हो जाए, लेकिन सांसद को 2500 रुपए का रोजाना भत्ता जरूर मिल जाता है। इस बार कुछ सांसदों ने ही यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सदन के स्थगन से जितना आर्थिक नुकसान हुआ है, उतनी राशि सांसदों से ही वसूल की जाए। सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। विपक्ष ने सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी रखा, जबकि उन्हें भी जानकारी थी कि संसद के भीतर चुनाव आयोग पर बहस नहीं की जा सकती। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का संवैधानिक विशेषाधिकार है, लेकिन विपक्ष ने सदन के भीतर और बाहर लगातार हंगामा किया और उसे अपना संवैधानिक अधिकार बताया। उस संदर्भ में वह बार–बार दिवंगत नेता अरुण जेतली को उद्धृत करता रहा। यदि संवैधानिक अधिकार के कारण ही संसद की कार्यवाही बाधित होती रहे और अंततरू उसे स्थगित करना पड़े, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यह कहना अर्द्धसत्य है कि सदन की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष का दायित्व है। यह कथन तब सही है, जब कार्यवाही में विपक्ष भी लगातार भागीदार बने। तभी बहस और चर्चाएं संभव हैं, तभी विधेयकों पर सामूहिक चर्चा कर उन्हें पारित करना संभव है। कहने को लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 14 बिल पारित किए गए। उन्हें 'हां' अथवा 'ना' के ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। उसके लिए संसद की क्या जरूरत है? ऑनलाइन गेमिंग सरीखे बिल, जो करीब 45 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है और करीब 20,000 करोड़ रुपए दांव पर हैं, बिना चर्चा के ही पारित कर लिए गए। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल महत्वपूर्ण बिल थे, लेकिन वे भी बिना चर्चा के पारित कर लिए गए। यदि संसद में ऐसा ही चलना है, तो सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है? लोकसभा की उत्पादकता 31 फीसदी और राज्यसभा की 35 फीसदी रही। लोकसभा में विधायी कार्य 2.9 घंटे और राज्यसभा में 13.1 घंटे ही हो सका। संसद सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला और 21 बैठकें हुईं। लोकसभा में 126 घंटे काम होना तय था, लेकिन 37 घंटे ही हो सका। लोकसभा में प्रश्नकाल मात्र 4. 7 घंटे और राज्यसभा में 1.2 घंटे ही चला। संसद का क्या औचित्य है कि सांसद मंत्री से सवाल ही न कर सके? यह सत्र उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के लिए भी याद किया जाएगा कि अचानक उन्हें इस्तीफा देने को बाध्य किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति न जाने कहां छिपे हैं कि उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है? उन्हें विदाई पार्टी भी नहीं दी गई! 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बहस तो हुई ।

सिंधु की पुकारः संप्रभुता की वापसी और गौरव की बहाली

अर्जुन राम मेघवाल

मानसून शब्द पूरे भारत में खुशी और गर्व का संचार करता है। यह नवाचार, नवीनीकरण और राष्ट्र के आर्थिक इंजन को तत्काल गति प्रदान करने का प्रतीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रचुर वर्षा के साथ मिलकर, इसकी नदियों को पुनर्जीवित करती है और देशभर में जल संसाधनों का विस्तार करती है। यह प्रगति के मौसम का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के साथ मिला दिए जाने पर देशभक्ति की एक अनूठी भावना का संचार करता है। लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक बार फिर आकांक्षी नागरिकों के लिए एक ऐसा खाका पेश किया जो एक विकसित भारत के निर्माण के व्यापक लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है। संसद के इस विशेष मानसून सत्र की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने इसे भारत का गौरवशाली सत्र बताया था। भारतीय सैनिकों का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारखानों पर निर्णायक प्रहार और सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का स्थगनकृये सब भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति के सबूत हैं और राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। फिर भी, सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए सरकार के राजी होने के बावजूद, विपक्ष ने बाधा डालने का रास्ता चुना और व्यापक जनहित की कीमत पर विचार–विमर्श को राजनीतिक नौटंकी में सीमित कर दिया। देश अरसे से स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने की कांग्रेस की पुरानी आदत का बोझ ढोता चला आ रहा है। विभाजन की दुखद विभीषिका से लेकर नेहरूवादी कूटनीति की महंगी पड़ने वाली विफलताओं तक, इतिहास गवाह है कि कैसे इन फैसलों ने भारत की मूल अवधारणा को ही कमजोर कर दिया। सिंधु जल संधि (1960) पर बारीकी से गौर करने पर, जनता और देश के विकास की कीमत पर तुष्टिकरण व अति–उदारता की एक ऐसी कहानी सामने आती है, जिसने राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं को निरंतर बाधित किया। यह घोर विडंबनापूर्ण है कि भारत के विकास से जुड़े हितों का त्याग एक ऐसे राजनीतिक आकलन से प्रेरित थे जिसने अपने नागरिकों के कल्याण से ऊपर पाकिस्तान के हितों को तरजीह दी। मूल रूप से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी), सिंधु नदी प्रणाली के जल का आवंटन पाकिस्तान के पक्ष में (80रू20) करती है। सिंधु नदी प्रणाली का उद्गम मुख्य रूप से भारत में है। इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी में बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी महत्वपूर्ण नदियों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे वैसे व्यापक जल संसाधन छिन गए जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विशाल शुष्क एवं सूखाग्रस्त इलाकों का कायाकल्प कर सकते थे। यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती, तो सुव्यवस्थित जल अवसंरचना इस इलाके के संपूर्ण विकास की तस्वीर को बेहतर बना सकती थी। हालांकि, इस महत्वपूर्ण त्याग से व्यापक कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीदें भ्रामक साबित हुईं। इस संधि के प्रक्रियात्मक संचालन ने चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन इसे दो महीने बाद, नवंबर में, संसद के समक्ष रखा गया और वह भी मात्र दो घंटे की औपचारिक चर्चा के लिए। जैसे ही इस संधि से जुड़े तथ्य सामने आए, इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में छपी प्रतिकूल टिप्पणियां सुर्खियों में छायी रहीं। इतने महत्वपूर्ण समझौते के प्रति संसदीय स्तर पर बरते गए इस जल्दबाजी भरे व्यवहार ने लोकतांत्रिक निगरानी, पारदर्शिता और तत्कालीन नेतृत्व की दुर्भावनापूर्ण मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस सीमित संसदीय पड़ताल के बावजूद, सिंधु जल संधि को भारतीय संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय एक युवा सांसद थे, ने चेताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का यह तर्क बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है कि पाकिस्तान की अनुचित मांगों के आगे झुकने से मित्रता और सद्भावना स्थापित होगी। संसद में 30 नवंबर 1960 को हुई बहस से पता चलता है कि सभी दलों ने इस संधि की आलोचना की थी। अधिकांश सदस्यों ने सरकार की आलोचना की थी और उस पर पाकिस्तान के सामने झुकने तथा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। राजस्थान से कांग्रेस सांसद श्री हरीश चंद्र माथुर, अशोक मेहता, ए.सी. गुहा, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद केटीके तंगमणि, सरदार इकबाल सिंह, बृजराज सिंह ने इस जल कूटनीति को लेकर स्पष्ट रूप से चिंताएं जाहिर की थी और इसके विफल होने से जुड़े नतीजों के बारे में अंदेशा जताया था। कुल मिलाकर, इस संधि को एकतरफा, न कि लेन–देन पर आधारित कहा जा सकता है। इस संदर्भ में, यह विडंबना ही थी कि लोकसभा में अपने उत्तर के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने माननीय सांसदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए और उन्हें कमतर भी आंका। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि संसदों द्वारा की गई आलोचना तथ्य और निहित विचारों से अनजान रहने पर आधारित है। उन्होंने (नेहरू) आगे कहा, मुझे इस बात का दुख है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को... एक ऐसा मामला जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है... इतने हल्के में और इतनी लापरवाही एवं संकीर्ण सोच के साथ लिया जा रहा है। इस संधि ने भारत के हितों को कुंद कर दिया और यह पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक उपलब्धि साबित हुआ। अयूब खान ने एक सार्वजनिक प्रसारण में स्वीकार किया था कि इस संधि की वैधता और गुण–दोष पाकिस्तान के विरुद्ध थे, लेकिन इस मामले में नेहरू की कूटनीतिक विफलता ने पाकिस्तान को बढ़त दिला दी। 4 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में अपने प्रसारण में, अयूब खान ने कहा था, अब जो समाधान हमें मिला है, वह आदर्श नहीं है... लेकिन यह सबसे अच्छा समाधान है जो हमें इन परिस्थितियों में मिल सकता था, इनमें से कई बिंदु, चाहे उनके गुण–दोष और वैधता कुछ भी हों, हमारे खिलाफ हैं। ये खुलासे आज भी राष्ट्रीय हित को गौण रखने के पीछे के मकसद पर सवाल खड़े करते हैं।

जैसा कि निरंजन डी. गुलाटी ने अपनी किताब इंडस वाटर ट्रीटीरू एन एक्सरसाइज इन इंटरनेशनल मीडिएशन में लिखा है, 28 फरवरी 1961 को खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने इस निराशा को स्वीकार करते हुए कहा थारू मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। इस संधि के बाद के घटनाक्रम में आया तीखा अंतर इस समझौते की असमानता को और भी गहराई से रेखांकित करता है। नेहरू की ढिलाई और राष्ट्रीय हित को दरकिनार करने की प्रवृत्ति समय के साथ भारी पड़ती गई। फरवरी 1962 में, श्वाशिंगटन पोस्ट्य को दिए एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री नेहरू ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को आगे की दिशा में एक बड़ा कदम और वास्तव में यह समझौता (कश्मीर के) क्षेत्रीय मुद्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण... बताया।

स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, शांति और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति की चाहत में कांग्रेस नेतृत्व ने भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा एवं समृद्धि के बजाय कूटनीतिक सुविधावाद को चुना। तुष्टिकरण की यह नीति कई मोर्चों पर राष्ट्रीय प्रगति के लिए हानिकारक साबित हुई। इस संधि से अपेक्षित मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लाभ कभी भी साकार नहीं हुए। इसके उलट, यह युद्धों और निरंतर सीमा–पार तनावों के रूप में दुर्भाग्य लेकर आई। जल–बंटवारे की इस सख्त व्यवस्था ने सूखे से लड़ने, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने और संवेदनशील इलाकों में कृषि को मजबूत करने हेतु अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की भारत की क्षमता को सीमित कर दिया। सत्ता–लोलुप शासकों ने आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की, जिससे भारत कमजोर हो गया। वास्तव में, यह संधि भारत के लिए जल कूटनीति की विफलता और पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक विजय थी। अब, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में एक और निर्णायक एवं साहसिक कदम उठा रही है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अंतिम रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना छोड़ नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट आह्वान राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी हैरू आतंकवाद और बातचीत साथ–साथ नहीं चल सकतेय पानी और खून साथ–साथ नहीं बह सकते। यह कदम पिछली नीतियों से अलग हटकर एक साहसिक और ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह केवल एक कूटनीतिक पुनर्संतुलन भर नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों और किसानों के हितों एवं संबंधित हितधारकों की आजीविका के अवसरों की रक्षा करने के भारत के संप्रभु अधिकार का एक दृढ़ रणनीतिक दावा है – जो पाकिस्तान की ओर से आने वाले लगातार सीमा पार खतरों के सामने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को सर्वोपरि रखता है। सिंधु जल संधि का स्थगन कूटनीति से कहीं आगे जाता हैकृयह विकासशील भारतञ्च2047 के लक्ष्य को साकार करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण फिर से हासिल करके, भारत जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत कर सकता है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकता हैकृजोकि एक विकसित राष्ट्र बनने की कुंजी है। यह निर्णय पुराने समझौतों द्वारा थोपी गई सहमतियों का अंत करता है और जल संप्रभुता को प्रगति की बुनियाद के रूप में स्थापित करता है। यह एक ऐसा साहसिक कदम है, जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और समावेशी विकास के मिशन के साथ गहराई से जुड़ा है।

आयोग ने सवालों के जवाब नहीं दिये

केसव

चुनाव आयोग की विशेष प्रेस कांफ्रेंस ने सिर्फ ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कद छोटा नहीं किया. महज चुनाव आयोग की साख नहीं घटी. ऐसी घटना हर हिंदुस्तानी का माथा नीचा करती है. मैं दुनिया भर में भारत की चुनावी प्रणाली का गुणगान करता था. इंग्लैंड को भारत के चुनाव आयोग से प्रक्रियाएं सीखने को कहा था. और अमेरिका को नसीहत दी थी कि बिना पक्षपात के चुनाव संपन्न

करना भारत की चुनावी व्यवस्था से सीखना चाहिए. पिछले कुछ वर्षों में उसी चुनाव आयोग की कारस्तानियों ने भारतीय चुनाव व्यवस्था की साख धूल में मिला दी है. चुनाव आयोग द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस का संदर्भ समझिए. उससे कोई दस दिन पहले संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहले महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े के आरोप लगाने के बाद कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट धांधली के गंभीर प्रमाण देश के सामने रख चुके थे. बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर गहन प्रश्न उठ चुके थे. जनमत सर्वेक्षण दिखा रहे थे कि चुनाव आयोग की साख अपने ऐतिहासिक न्यूनतम से नीचे गिर चुकी है. बिहार के सभी विपक्षी दलों के मुख्य नेता रविवार को वोटबंदी के विरुद्ध 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत करने वाले थे. चुनाव आयोग ने ठीक उसी दिन सरकारी अवकाश के बावजूद प्रेस वार्ता बुलायी. तभी अंदेशा हो गया था कि यह विपक्ष की हेडलाइन खाने का खेल है. मगर कहीं उम्मीद बची थी कि आयोग चुनाव व्यवस्था की साख बचाने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकता है. उम्मीद इस बात से भी बंधी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडियाकर्मियों को आने की छूट दी गयी, सवालों को सेंसर नहीं किया गया. पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया और जो नहीं कहा गया, वह निर्वाचन आयोग के इतिहास में शर्मनाक अध्याय की तरह दर्ज किया जायेगा.। इस प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त का शुरुआती वक्तव्य किसी संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष के बयान की बजाय एक राजनेता के भाषण की तर्ज पर था. यह कयास लगना स्वाभाविक था कि उनका भाषण कहीं और से लिखकर आया है. गनीमत समझिए कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार की तरह तुकबंदी की कोशिश नहीं की, लेकिन सस्ते फिल्मी डायलॉग पर अपना हाथ जरूर आजमाया. वह मैच के अंपायर कम और खिलाड़ी ज्यादा दिखाई दिये.।बेशक पत्रकार सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र थे, पर मुख्य चुनाव आयुक्त भी किसी सवाल का जवाब देने या न देने के लिए स्वतंत्र थे, किसी सवाल के जवाब में कुछ भी प्रासंगिक–अप्रासंगिक बोलने के लिए स्वतंत्र थे. सवाल था कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा, तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं. जवाब था कि स्थानीय वोटर ही आपत्ति दर्ज कर सकता है. तो क्या अनुराग ठाकुर वायनाड के स्थानीय वोटर हैं? सवाल था कि अगर एफिडेविट देने से जवाब मिलता है, तो सपा ने जो एफिडेविट दिया था, उसका कोई जवाब क्यों नहीं मिला. जवाब था कि ऐसा कोई एफिडेविट नहीं दिया गया था. यह उत्तर सफेद झूठ निकला. सवाल था कि वोटर लिस्ट डिफेक्टिव थी, तो क्या मोदी जी की सरकार वोट धांधली के आधार पर बनी है. उत्तर था कि निर्वाचक होने और मतदाता होने में फर्क है. जिनका मतदाता सूची में गलत नाम था, उन्होंने वोट नहीं दिया. इस अद्भुत निष्कर्ष का आधार नहीं बताया गया। सवाल था कि एसआइआर से पहले पार्टियों से राय–मशविरा क्यों नहीं हुआ. इसका जवाब नहीं मिला. सवाल था कि चुनाव वाले साल में इंटेंसिव रिवीजन न करने की चुनाव आयोग की अपनी ही लिखित मर्यादा क्यों तोड़ी गयी? जवाब में फूहड़ जुमला मिला रू रिवीजन चुनाव से पहले करवायें या बाद में? सवाल था कि इतनी हड़बड़ी में बारिश, बाढ़ के बीच एसआइआर क्यों करवाया गया. जवाब था कि इसी महीने में 2003 में भी कराया गया था. बात गलत थी, क्योंकि 2003 में रिवीजन से कई महीने पहले तैयारी की गयी थी, और तब न फॉर्म था, न दस्तावेज इकट्ठा करने थे. कई पत्रकारों ने सीधे तथ्य मांगे. कितने लोगों ने फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं जमा करवाया? बीएलओ ने कितने फॉर्म को 'नॉट रिकमेंडेड' श्रेणी में डाला? किस आधार पर? बिहार में एसआइआर के दौरान जून–जुलाई के बीच कितने नाम जोड़े गये? एसआइआर के जरिये पुरानी वोटर लिस्ट में कितने विदेशी घुसपैठिये निकले? जवाब में मिला सिर्फ सन्नाटा.। बीच–बीच में सन्नाटे को तोड़ती थी लफ्फाजी. 'सात करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं' जैसा बेमानी डायलॉग. शाम को देर तक वोटिंग के प्रमाण के रूप में मांगी गयी सीसीटीवी वीडियो को माताओं–बहनों की इज्जत से जोड़ने की फूहड़ कोशिश. मशीन रीडेबल डाटा की मांग को खतरनाक बताने का हास्यास्पद प्रयास. और देश के सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिमाकत कि बिहार के हर गांव–मोहल्ले में बीएलओ ने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला कर उन्हें यह सूची दी कि कौन मृतक हैं,।

विपक्ष की हार उसकी अपनी कमियों के कारण

अजीत द्विवेदी

पहले एक चुटकुले से शुरुआत करते हैं, फिर महान लेखक कृश्नचंदर की किताब श्एक गधे की आत्मकथाय का एक संदर्भ और तब राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन की चर्चा करेंगे। चुटकुला ऐसे हैरू एक व्यक्ति वोट डालने जाता है। वोट डाल कर मतदान करा रहे अधिकारी से पूछता है– देखना मेरी पत्नी आशा देवी वोट डाल कर चली गईं? महिला अधिकारी सूची देख कर कहती है– हां, एक घंटे पहले ही वोट डाल कर चली गईं। व्यक्ति आह भरते हुए कहता है– इसका मतलब है कि एक घंटे पहले आते तो भेंट हो जाती। अधिकारी हंसती है और पूछती है– मजाक कर रहे हैं, क्या घर में आप लोगों की भेंट नहीं होती है? व्यक्ति कहता है– मेरी पत्नी को मरे हुए 15 साल हो गए लेकिन हर बार हमसे एक घंटा पहले आकर वोट डाल जाती है! यह एक व्यंग्य है, जो हम लोग कई दशकों से सुन और सुना रहे हैं। इसका मतलब है कि मतदाता सूची में मृत लोगों के नाम होते हैं और उनका वोट कोई और डालता है। यह प्रक्रिया आजादी के बाद से ही चल रही है। भारत की चुनाव व्यवस्था पर तंज करने वाला यह व्यंग्य इसलिए याद आया क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मिले, जिन्हें मृत बता कर उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, मृत व्यक्तियों के साथ चाय पीकर बहुत मजा आया। सवाल है कि जब मृत व्यक्ति वोट डाल सकता है तो जीवित व्यक्ति को मृत बता कर उसका नाम काट देना कौन सी बड़ी बात है? उनको कुछ समय पहले बनी कागजय फिल्म देखनी चाहिए। सतीश कौशिक निर्देशित और पंकज त्रिपाठी के बेहतरीन अभिनय वाली इस फिल्म में एक मृत घोषित कर दिया गया व्यक्ति अपने को जीवित साबित करने के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी जिस घटना पर आधारित है वह दशकों पुरानी, तब देश में कांग्रेस का ही शासन होता था। देश के कई राज्यों में शासन की व्यवस्था जीवित लोगों को मृत घोषित कर देती है और उसके बाद वे अपने को जीवित साबित करने के लिए बरसों संघर्ष करते हैं। लगता है इस तरह की कहानियां भी राहुल गांधी ने नहीं सुनी हैं। तभी वे ऐसे लोगों से मिल कर आश्चर्यचकित हो रहे थे, जिनको मृत बता कर मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उनका आश्चर्य ऐसे बच्चे की तरह है, जिसको अभी आंखों की रोशनी मिली हो और वह ट्रेन देख कर विस्मित हो रहा हो! बहरहाल, महान लेखक कृश्नचंदर की चर्चित किताब है श्एक गधे की आत्मकथाय। इसमें गधा पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिलता है। उससे पहले वह उनकी सरकार के कुछ और मंत्रियों से भी मिलता है। उससे पहले उसकी मुलाकात दिल्ली के एक इलाके के थानेदार से होती है। थानेदार इस पर आश्चर्यचकित होता है कि गधा इंसानों की तरह बोल रहा है। वह कहता है कि उसने बहुत सारे इंसानों को तो गधों की तरह बोलते सुना है लेकिन पहली बार किसी गधे को इंसानों की तरह बोलते सुन रहा है। कहने का मतलब है कि गधा आदमी की तरह बोले तो आश्चर्य होता है लेकिन आदमी गधों की तरह बोलें, को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी का आश्चर्य उसी तरह का है। यानी मृत लोग जीवित लोगों की तरह मतदान करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन जीवित लोगों को मृत बता कर वोट काट दिया जाए तो वह बड़े आश्चर्य की बात है! राहुल गांधी से लेकर योगेंद्र यादव और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज इस बात पर ऐसे हैरान हो रहे थे, जैसे यह कोई अनहोनी बात हो। असल में यह कोई अनहोनी बात नहीं है। मतदाता सूची में ऐसी खामियां होती हैं और यह व्यवस्था की वजह से होती है। चुनाव आयुक्त इसके लिए खासतौर से निर्देश नहीं जारी करते हैं। वैसे ही जैसे कई राज्यों में जीवित लोगों के नाम पेंशन की सूची से कट जाता है और वे भागदौड़ करते रहते हैं अपने को

जीवित साबित करने के लिए। इसके लिए भी कहीं ऊपर से निर्देश नहीं आता है। सोचें, कोई 15 साल पहले जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था तो बिहार में शाहरूख खान और सलमान खान के भी आधार कार्ड बन गए। क्या यूआईडीएआई के तत्कालीन प्रमुख नंदन नीलेकणी ने इसके लिए निर्देश दिए होंगे! एक समय बिहार में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का वोटर कार्ड भी बन गया था तो क्या तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने इसके लिए निर्देश भेजा होगा? ऐसे ही बिहार में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण का ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था। तो क्या बिहार के परिवहन मंत्री या परिवहन सचिव ने नीचे आदेश देकर प्रभाकरण का लाइसेंस बनवाया? असल में यह व्यवस्था की खामी है कि कुछ जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाते हैं तो कुछ मृत व्यक्तियों के नाम सूची में रह जाते है या किसी के पिता का या पति का नाम गलत हो जाता है। यह काम चुनाव आयुक्त निर्देश देकर नहीं कराते हैं। बिहार में एसआईआर के पहले चरण के बाद जितनी शिकायतें सामने आई हैं उनको देख कर यही लग रहा है कि नीचे के कर्मचारियों की लापरवाही से कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। ध्यान रहे एक सितंबर से 18 सितंबर के बीच सिर्फ 45 हजार शिकायतें आयोग को मिली हैं। यह काटे गए 65 लाख नामों के एक फीसदी से भी कम है। तभी कुल मिला कर विपक्ष की कहानी में दम नहीं दिख रहा है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में दुनिया भर की गड़बड़ियां हुई हैं। बूथ लेवल अधिकारियों ने घर में बैठ कर मनमाने तरीके से फॉर्म भरे हैं और उन्हें जमा करा दिया है। लेकिन क्या पहले भी इसी तरह से मतदाता सूची नहीं बनती थी? क्या पहले इसी तरह से आधार नहीं बने हैं, क्या इसी तरह से जनगणना नहीं होती है और क्या इसी तरह से बिहार में जाति गणना के फॉर्म नहीं भरे गए थे? बिहार या कहीं के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रक्रिया क्या रही। अंत नतीजा यह है कि सवा सात करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। अब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कैसे किसका नाम आया और कैसे किसका नाम कट गया। अगर 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जिनमें कुछ नाम गलत तरीके से कट गए हैं तो उनसे भी बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनके पास समय भी है कि वे फॉर्म छह भर कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों को क्या कहा जाए? उनको लगता है कि बिहार आंदोलन की धारती है तो किसी भी बात पर आंदोलन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आंदोलन के लिए मुद्दा भी होना चाहिए और नेता भी जरूरी है। इस बार दोनों नहीं हैं। हर हार के बाद राहुल गांधी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता कभी ईवीएम को दोष देते हैं तो कभी मतदाता सूची में गड़बड़ी को तो कभी चुनाव आयोग की धांधली को। इसमें भी समस्या नहीं है। विपक्ष को ऐसे आरोप लगाने चाहिए। लेकिन मुश्किल तब होती है, जब विपक्षी पार्टियां सचमुच मानने लगती हैं कि वे किसी धांधली या गड़बड़ी से हारी हैं और अगर गड़बड़ी नहीं होती तो वे चुनाव जीत जाते। क्या सचमुच विपक्ष की हार का मामला इतना सरल है? हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियां होती हों लेकिन विपक्ष की हार उसकी अपनी कमियों के कारण हैं और भाजपा की जीत सिर्फ चुनावी धांधली की वजह से नहीं है। जहां तक व्यवस्था में गड़बड़ी का सवाल है तो उस मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है।

60 दिन पहले ही चार गुनी महंगी हो गईं फ्लाइटें, सफर मुहाल

लखनऊ, (संवाददाता)। दीपावली पर दिल्ली, मुंबई से लखनऊ आने वालों के लिए सफर का संकट बढ़ता जा रहा है। एक ओर ट्रेनों में रिग्रेट होने से सीटें नहीं बुक हो रही हैं, दूसरी ओर विमानों का किराया करीब दो महीने पहले ही चार गुना तक महंगा हो गया है।

जो त्यौहार करीब आने पर सात से आठ गुनी तक महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। 20 अक्तूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाना है। ऐसे में दिल्ली व मुंबई में बड़ी संख्या में रहने वाले लखनऊवासियों की वापसी 18 से ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि लखनऊ आने के लिए यात्रियों को अभी से पसीने छूटने लगे हैं। उन्हें ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही हैं और विमान का किराया आसमान को छूने लगा है। नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की सीधी उड़ान एआई–2477 का टिकट 4747 रुपये में मिल रहा है। इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट 6ई–2258 का टिकट 4831 रुपये में उपलब्ध है। जबकि एयर इंडिया व इंडिगो की अन्य उड़ानों के टिकट 72 सौ रुपये तक पहुंचे हैं। आम दिनों में तीन से चार हजार रुपये में टिकट मिल जाते हैं। त्यौहार करीब आने तक यह किराया 12 से 15 हजार रुपये तक पहुंच जाएगा।

मुंबई की ट्रेनों में रिग्रेट, दिल्ली की महंगी चेयरकार खाली

दीपावली पर मुंबई से लखनऊ आने वाली लगभग सभी ट्रेनों में रिग्रेट चल रहा है। पुष्पक एक्सप्रेस, अवध, कुशीनगर, एलटीटी सीतापुर, एलटीटी गोरखपुर आदि ट्रेनों की स्लीपर से लेकर एसी बोगियों तक में रिग्रेट चल रहा है, जिससे यात्रियों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली से लखनऊ आने वाली चेयरकार ट्रेनों में सीटें खाली हैं, लेकिन उनका किराया महंगा है। दिल्ली से आने वा ली वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयरकार में 702 तक सीटें खाली हैं। तेजस एक्सप्रेस की चेयरकार में 388 सीटें, शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार में 289 तक सीटें रिक्त हैं। जबकि एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल जैसी रेगुलर ट्रेनों में रिग्रेट चल रहा है।

चार गुनी महंगी हुईं उड़ानें

ऐसे ही मुंबई से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस आईएक्स–1219 का टिकट 16241 रुपये में मिल रहा है। इंडिगो की डायरेक्ट उड़ान 6ई–5379 का टिकट 18399 रुपये पहुंच गया है। जबकि आम दिनों में पांच हजार रुपये में टिकट मिल जाता है। इतना ही नहीं बंगलुरु से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस आईएक्स–1230 का टिकट 17930 रुपये पहुंच गया है। इंडिगो की 6ई–451 का टिकट 17333 रुपये हो गया है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव के समर्थन के लिए युवाओं-छात्रों को जोड़ेगी भाजपा

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र–एक चुनाव अभियान के समर्थन के लिए छात्रों और युवाओं को जोड़ेगी। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रविवार को अभियान को गति प्रदान करने के लिए आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों के संदर्भ में व्यापक विचार–विमर्श करते हुए रणनीति तय की गई। पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान समिति के प्रदेश के सह संयोजक व एमएलसी अनूप गुप्ता व प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें छात्रों व युवाओं को अभियान के साथ जोड़ते हुए सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉलेजों आदि में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है लोकतंत्र को अनावश्यक खर्च, बार–बार होने वाले चुनाव और राजनीतिक अस्थिरता से मुक्त किया जाए। इसके लिए राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ एक राष्ट्र–एक चुनाव आवश्यक है। आर्थिक नीतियों में निरंतरता, व्यापार और रोजगार को गति देने के लिए एक देश–एक चुनाव समय की मांग है। इसके लिए लोकमत तैयार करना है ताकि इस मुहिम में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। गांव, गली, शहरों, खेत, खलिहानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में चर्चा के साथ ही युवाओं को भी जोड़ना है। प्रदेश टोली के सदस्यों पर अभियान की सफलता की जिम्मेदारी है। अभियान से व्यापारियों को भी जोड़ने के लिए योजना बनाकर काम करना होगा। वहीं, अनूप गुप्ता ने कहा कि अभी तक प्रदेश में जो भी अभियान और कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में आयोजित किए गए हैं, उन्हें समाज के हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ है। बैठक में स्टूडेंट फॉर वन–नेशन–वन–इलेक्शन के संदर्भ में व्यापक चर्चा हुई।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरठ मंडल में 8 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। प्राचीन मंदिरों, गुरुद्वारों और बौद्ध विहारों जैसे धार्मिक स्थलों की भव्यता को पुनर्स्थापित करने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरठ मंडल की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के तहत गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में धार्मिक पर्यटन विकास पर कुल सात करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।पर्यटन मंत्री ने बताया कि विभागीय प्रयासों से श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। हाल के वर्षों में धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थों के साथ–साथ अब श्रद्धालुओं का रुझान नए गंतव्यों की ओर भी बढ़ रहा है। इसी क्रम में एनसीआर क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण व पर्यटक सुविधाओं का विकास विभाग की प्राथमिकता में शामिल है।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्राम नगली वाजिदपुर स्थित प्राचीन बेरी वाला मंदिर और जेवर विधानसभा क्षेत्र के सिरसा माचीपुर गांव में मां भूड़ावाली देवी मंदिर के पर्यटन विकास के लिए एक–एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नोएडा विधानसभा क्षेत्र की अक्षरधाम कॉलोनी स्थित धम्मदीप बौद्ध विहार और ग्रेटर नोएडा के सूरजनगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के विकास व सौंदर्यीकरण के लिए 50–50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।गाजियाबाद जिले में भी पर्यटन विकास को लेकर विशेष पहल की गई है। जिले के प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार कराने के लिए जय भीम पार्क (वार्ड–01, कृष्णा नगर बागू), मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के असालतनगर गांव स्थित श्री हनुमान मंदिर, साहिबाबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड–31 सिहानी स्थित प्राचीन शिव मंदिर तथा मोदीनगर विधानसभा के निवाड़ी स्थित चुकाय वाली माता मंदिर के विकास पर क्रमशः एक–एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास होगा।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की आत्मनिर्भरता अहम : अनिल राजभर

लखनऊ, (संवाददाता)। ग्रेटर नोएडा के होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित रोजगार मिशन इंडस्ट्री कनेक्टद्2025 कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष 25 हजार युवाओं को विदेशों में और 3 लाख युवाओं को देश के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है।इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार एक–दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं को तभी रोजगार से जोड़ा जा सकता है जब उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। ब्रिक्स चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हरवंश चावला ने जानकारी दी कि रूस को इस वर्ष भारत से लगभग एक लाख कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में भी बड़ी संख्या में श्रमिकों की मांग है और उत्तर प्रदेश इस आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम. के.एस. सुन्दरम ने बताया कि सरकार की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के चलते प्रदेश में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई है। सेवायोजन निदेशक नेहा प्रकाश ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम की महत्ता और विभागीय गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। अपर निदेशक पी.के. पुंडीर ने रोजगार संगम पोर्टल और अन्य योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त निदेशक शैलजा सिंह ने एनसीएस पोर्टल की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी, प्रमुख सचिव डॉ. एम.के.एस. सुन्दरम, निदेशक नेहा प्रकाश और अपर निदेशक पी.के. पुंडीर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस मौके पर मंत्री अनिल राजभर ने विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित बुकलेट का विमोचन भी किया।कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों, शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उद्योगों व संस्थानों के बीच साझेदारी को नई दिशा देने का संदेश दिया।

बारिश के चलते यहां कक्षा एक से आठ तक बंद किए गए सभी स्कूल

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के रायबरेली में भारी बारिश को देखते हुए आज यानी सोमवार को कक्षा एक से आठ तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम हर्षिता माथुर ने बीएसए को निर्देश दिए हैं। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को इस पर अमल करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा सक्रिय हुए मानसून के बाद बीते तीन दिनों में प्रदेश के दक्षिणी और तराई इलाकों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के पूर्वी और तराई के 30 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 26 अगस्त से अगले पांच दिनों के लिए मानसूनी बारिश में कमी आएगी। रविवार को दक्षिणी जिले सोनभद्र में सर्वाधिक 130 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं मिर्जापुर में 105 मिमी, भदोही में 98 मिमी और प्रयागराज में 72 मिमी बारिश हुई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को यूपी के पूर्वी और तराई इलाके के 30 जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश के संकेत हैं। 26 अगस्त से अगले चार–पांच दिनों के लिए मानसूनी बारिश धीमी पड़ेगी।

संक्षिप्त खबरें

सीएम ग्रिड के तहत महानगर, गोल मार्केट में निर्माण कार्यों का निरीक्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने रविवार को सीएम ग्रिड योजना के तहत महानगर एवं गोल मार्केट क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, मुख्य अभियंता (सिविल) महेश वर्मा व अभियंत्रण विभाग के अभियंता मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी नगर आयुक्त को दी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने मौके पर अधिकारियों के साथ सड़कों की गुणवत्ता, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न हो और उपयोग की जा रही सामग्री की नियमित जांच की जाए।

प्रशासन अलर्ट, मौके पर पहुंचे अफसर, करवाई गई सफाई

लखनऊ, (संवाददाता)। जानकीपुरम सेक्टर–सात विस्तार क्षेत्र में डायरिया के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रविवार को नगर आयुक्त सहित कई अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सफाई का जायजा लिया। साथ ही घर–घर क्लोरीन टैबलेट पहुंचाने व नालियों में ब्लीचिंग छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से उपरोक्त इलाके में डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने स्वास्थ्य एवं नगर निगम की टीमों के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनबी सिंह सहित अपर जिलाधिकारी फाइनेंस, अपर नगर आयुक्त, जीएम जलकल आदि उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने पेयजल आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने पाइपलाइन की गहन जांच कराई, ताकि कहीं से भी लीकेज या दूषित जल की आपूर्ति न हो। पेयजल की शुद्धता बनाए रखने के लिए हर घर तक क्लोरीन की टैबलेट पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराते हुए नालियों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि प्राथमिकता नागरिकों का स्वास्थ्य है। इसीलिए डायरिया जैसे मौसमी रोगों पर रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

पाइपलाइन खराबी तत्काल करें दूर

निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि जलकल विभाग की टीमें पाइपलाइन में किसी भी प्रकार की खराबी को तत्काल ठीक करें। साथ ही सफाईकर्मियों को रोजाना नालियों की साफ–सफाई करने व ब्लीचिंग के छिड़काव को कहा गया है। निगम की ओर से क्षेत्रीय लोगों से अपील की गई है कि वे उबालकर पानी पिएं और स्वास्थ्य समस्या होने पर तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

भाजपा राज में खाद संकट, किसान असुरक्षित और लोकतंत्र खतरे में – अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसान खाद के लिए दर–दर भटक रहे हैं। पूरे प्रदेश में खाद का गहरा संकट है। कई जिलों में बुजुर्ग किसानों की लाइन में खड़े–खड़े मौत तक हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। खाद संकट के लिए पूरी तरह भाजपा सरकार जिम्मेदार है।उन्होंने कहा कि किसानों पर चौतरफा संकट मंडरा रहा है। एक ओर फसलों के लिए खाद नहीं है तो दूसरी ओर जंगलों से सटे जिलों में जंगली जानवरों के हमलों से किसानों और ग्रामीणों की जान जा रही है। बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर और बलरामपुर में गुलदार, भेड़िया और बाघ के हमलों से किसानों और बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार सदन से सड़क तक किसानों की आवाज उठा रही है, लेकिन भाजपा सरकार को सुनाई ही नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची।रविवार को सपा मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने और उनके मर्जर पर सरकार ने विधान सभा में झूठा दावा किया था कि कोई स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन जमीन पर सच्चाई सामने है कि बंद किए गए स्कूल अब तक नहीं खुले। यही इस सरकार का चरित्र हैकृझूठ और केवल झूठ।उन्होंने कहा कि सरकार अब पीडीए पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को भी निशाना बना रही है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की तैयारी हो रही है। यह भाजपा का उत्पीड़न और अन्याय है।चुनाव और वोटिंग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वोट चोरी करती है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि वोट बनवाना, उसे जोड़वाना, मतदान कराना और गिनती तक में नजर रखना अब कार्यकर्ताओं और जनता की बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने खुलासा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शपथपत्र देकर बताया था कि 18 हजार वोटर लिस्ट से नाम गलत तरीके से काटे गए, लेकिन अभी तक महज 14 मामलों की जांच हुई। अखिलेश ने सवाल किया कि अगर मतदाताओं को मृत दिखाया गया तो उनका मृत्यु प्रमाणपत्र कहां है?नए विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह सिर्फ क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने और नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का षडयंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अपने नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए, जबकि सपा नेताओं जैसे आजम खां, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी को फर्जी मामलों में जेल भेज दिया।सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह समझ से परे है कि जो मुख्यमंत्री से मिल रहा हो, उसे समाजवादी पार्टी से खतरा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है क्योंकि राज्य सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का कामकाज पूरी तरह विफल है। भाजपा कार्यकर्ता जमीन कब्जा, तालाब हड़पने और अपराध–भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी बुलडोजर नहीं चलता। उन्होंने कहा कि जैसे–जैसे चुनाव करीब आएगा, भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में जूता ही रह जाएगा।उन्होंने कहा कि जनता अब पीडीए के साथ है और बदलाव चाहती है। सपा का संकल्प है कि भाजपा की अन्यायी और भ्रष्टाचारी सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली और समृद्धि समाजवादी विचारधारा, सेकुलरिज्म और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव है। संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा, जिन्हें भाजपा लगातार कमजोर कर रही है। भाजपा को सत्ता से बाहर करना ही लोकतंत्र और संविधान बचाने का रास्ता है।

राजनीतिक भागीदारी से मजबूत होगा नेतृत्व

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में रविवार को भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की बैठक हुई। इसमें समाज को शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव में तेली समाज के बैनर पर लड़ने का एलान किया गया। कैसरबाग स्थित गांधी भवन में हुई बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। तभी समाज का नेतृत्व मजबूत होगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण साहू ने युवाओं से शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। कहा, उच्च शिक्षा ग्रहण करके ही समाज के बच्चे बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। युवा प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर साहू ने कहा कि अगर समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली तो हम अपने बैनर पर चुनाव लड़ने को बाध्य होंगे। वक्ताओं ने समाज के लोगों से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें तेली समाज की बहुलता वाली हैं। अगर समाज की अनदेखी हुई तो महासभा इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बैठक में प्रदेश महामंत्री संपूर्णानंद गुप्ता, प्रदेश महिला अध्यक्ष अर्चना साहू, मनोज कुमार साहू समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए।

गोवंश खरीदने जा रहे रेलयात्री का 10.50 लाख रुपये जब्त

लखनऊ, (संवाददाता)। सद्भावना एक्सप्रेस से गोवंश खरीदने जा रहे रेलयात्री के पास मिले 10.50 लाख रुपये जब्त कर लिए गए हैं। यात्री शहजाद ने आय का स्रोत नहीं बताया, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। साथ ही उसे नोटिस दिया गया है कि साक्ष्य प्रस्तुत करे। बागपत निवासी शहजाद जानवरों की खरीदफरोख्त करता है। वह बीती शुक्रवार शाम सद्भावना एक्सप्रेस से हापुड़ से लखनऊ आ रहा था। उसके पास जनरल टिकट था, जिस पर वह स्लीपर बोगी में यात्रा कर रहा था। लखनऊ पहुंचने के बाद उसे आजमगढ़ जाना था, जहां गोवंश की खरीदारी करनी थी। टीटीई की जांच के दौरान उसके पास से साढ़े दस लाख रुपये बरामद किए गए। पैसे के बाबत जब शहजाद कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो टीटीई ने इसकी सूचना जीआरपी कंट्रोल रूम को दी। ट्रेन के चारबाग स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ ने शहजाद को हिरासत में लिया और आयकर विभाग को सूचना दी। विभाग ने पूछताछ की, जिसमें वह स्रोत नहीं बताया, जिसके चलते धनराशि जब्त कर ली गई है। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी होने के बाद यात्री को छोड़ दिया गया है। अब आयकर अधिनियम के तहत ही यात्री पर कार्रवाई होगी।

कॉलोनी के पार्क में कूड़ा डंपिंग के विरोध में उतरे लोग

लखनऊ, (संवाददाता)। आईआईएम रोड स्थित बालाजी इनक्लेव वासियों ने रामकी कंपनी की ओर से कॉलोनी में कूड़ा डंप करने को लेकर विरोध–प्रदर्शन किया। हालांकि रामकी कंपनी ने मामले से इनकार किया है। कॉलोनी निवासी रवि द्विवेदी ने बताया कि एक ओर लखनऊ में स्वच्छता अभियान चल रहा है। बड़े–बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कूड़ा उठाने वाली कंपनी रामकी ने कॉलोनी के एक पार्क के अंदर कूड़ा डंपिंग यार्ड बना दिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को असुविधाएं उठानी पड़ रही हैं। विरोध के बावजूद कूड़ा नहीं उठाने के चलते रविवार को प्रदर्शन किया गया।

30 डग्गामार बसें सीज, कईयों का हुआ चालान

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में दौड़ रही डग्गामार बसों व अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। रविवार को आरटीओ प्रवर्तन की टीम ने कुल 31 वाहनों को सीज किया, जिसमें 30 बसें व एक कार शामिल है। परिवहन विभाग की ओर से पिछले कई दिनों से डग्गामार वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात कुमार पांडेय ने बताया कि शहर के विभिन्न चौराहा के आसपास से विभिन्न मार्गों पर परमिट शर्तों का उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही बसों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को अहिमामऊ चौराहे से आजमगढ़ जा रही तथा कमता चौराहे के पास से अयोध्या जाने वाली 13 बसें, मड़ियांव भिटौली से सीतापुर मार्ग पर चलने वाली 12 बसें एवं अवध चौराहा से आगरा एक्सप्रेसवे जा रही छह बसों को सीज किया गया है। कुल 30 बसें व एक आर्टिगा कार सीज को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सीज किया गया है। वाहनों को वृंदावन स्थित पी–4 पार्किंग, कैसरबाग स्थित अवध डिपो कार्यशाला, थाना मड़ियांव एवं बख्शी का तालाब थाना में निरुद्घ किया गया है। इसके अलावा तीन बसों के चालान किए गए हैं। सभी बसें परमिट के नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई चलती रहेगी।

एकता और जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। निषाद नगर रेतिया पण्डारेवीर मंदिर पर निषाद समाज की ओर से एकता और जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल निषाद तथा संचालन सुनील निषाद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में घुमंतू जन जाति भारत सरकार के सदस्य भरत भाई पटनी तथा प्रवीण गोगे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष श्यामवीर सिंह, मत्स्य पूजन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी कैलाश नाथ निषाद एवं समाज कल्याण अधिकारी रणविजय सिंह शामिल हुए।मुख्य अतिथियों का स्वागत निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद द्वारा अंग वस्त्र एवं बुके देकर किया गया। राहुल निषाद के नेतृत्व में समाज की ओर से भारत भाई पटनी को एक ज्ञापन भी दिया गया ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश सहित भारतवर्ष में निषाद समाज विभिन्न उपजातियां जैसे केवट,बिंद, धीमर, मल्लाह, गोंड, कश्यप, भुजवा, तुरहा, खरवार, मांझी आदि नाम से बंटा हुआ है इन सभी की मूल उत्पत्ति परंपरा व्यवसाय एवं सांस्कृतिक आधार एक ही है लेकिन प्रशासनिक अभिलेख और जनगणना में इन्हें अलग–अलग दर्ज किया जाता है जिससे समाज को उनकी वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक न्याय का अधिकार नहीं मिल पाता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि निषाद समाज की सभी उपजातियां को एकीकृत कर निषाद नाम से राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रेषित करने की कृपा की जाए।इस निर्णय से समाज को एक पहचान मिलेगी और आगामी जनगणना में भी निषाद की सभी उपजातियां एक ही जाति के रूप में दर्ज हो सकेंगी। इस कार्यक्रम में निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद, राहुल निषाद, अमन निषाद उर्फ आकाश, श्याम बाबू निषाद, कुश निषाद, ध्रुव निषाद अमर निषाद पार्षद लवकुश निषाद, हरिकिशन निषाद, जिलेश निषाद रोहित निषाद प्रधान,विकास निषाद नंदू निषाद आदि लोग मौजूद रहे।

सभी वाहन स्वामी वाहन एंव सारथी वेबसाइट पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस व मोबाइल नंबर को कराये अंकित - एआरटीओ

अयोध्या। सभी वाहन स्वामी वाहन एव सारथी में अपने ड्राइविंग लाइसेंस व मोबाइल नंबर को अंकित करवा ले जिससे समय–समय पर आपको वहां संबंधित सूचना आपके मोबाइल पर मिलती रहे। इस बात की जानकारी

देते हुए एआरटीओ प्रवर्तनध प्रशासन डॉक्टर आर पी सिंह ने बताया कि इससे वाहन स्वामियों को अपनी बहन के बारे में चाहे वह पंजीकरण हो चाहे बीमा इसके साथ–साथ चालान आदि की सूचना समय–समय पर मिलती रहेगी। बताया कि समय–समय पर सूचना मिलने से वाहन स्वामी समय रहते बिना किसी जुर्माने के बीमा चालान आदि समय से भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी भी कुछ वाहन स्वामी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर इस पर नहीं पड़ा है और अगर पड़ा है तो संबंधित मोबाइल नंबर बंद है या फिर गलत है।जिसके कारण सेवा संबंधी अलर्ट, वैधानिक नोटिस एवं अन्य महत्वपूर्ण सदेश इच्छित व्यक्तियों तक समय से नहीं पहुँच पा रहें हैं।उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपील किया कि समस्त वाहन स्वामी एवं ड्राइविंग लाइसेंस धारक यह सुनिश्चत कर ले कि वाहन एवं सारथी पर उनके मोबाइल नंबर सही अंकित है तथा जिन वाहन मालिको और ड्राइविंग लाइसेस धारकों के मोबाइल नंबर वाहन एवं सारथी पर अपडेट नहीं है वे शीघ्र ही परिवहन विभाग की वेबसाइटीजजचेरूध्चंतपअींद.हवअ.पद पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें।

वरिष्ठ नागरिकों का पब्लिक सेवा संस्थान ने होटल मे किया सम्मान

(डॉक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय पब्लिक सेवा संस्थान ने अपने बैनर तले तथा शुभारंभ होटल के प्रायोजन में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का सफल आयोजन किया।कार्यक्रम का शुभारंभ शुभारंभ होटल की डायरेक्टर तनुजा दुबे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिसके पश्चात वे उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।इस अवसर पर संस्था द्वारा आमंत्रित गणमान्य अतिथियों का बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। लगभग 60 से 70 वरिष्ठ नागरिकों को इस सम्मान समारोह के दौरान उनके योगदान और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों के लिए सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में पब्लिक सेवा संस्थान के मुख्य ट्रस्टी राकेश श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिला कोऑर्डिनेटर रामकुमार, मुख्य सलाहकार डॉ. नीति श्रीवास्तव, महासचिव बबीता यादव सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए संस्था की प्रशंसा की।पब्लिक सेवा संस्थान द्वारा अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में लगातार समाज सेवा के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो क्षेत्र के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह इस समर्पित प्रयास की एक जीवंत मिसाल है, जहाँ बुजुर्गों के योगदान को सलाम करते हुए उनकी गरिमा व सम्मान को और मजबूती दी गई।समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े लोग इस पहल को सराहते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय समुदाय में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ–साथ बुजुर्गों को सशक्त करने का माध्यम बनते हैं।

53वें वर्ष की श्री बाल रामलीला नाट्य कला मंदिर चौक की तैयारी शुरू, कमेटी की पहली बैठक संपन्न

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

श्री बाल रामलीला नाट्य कला मंदिर, चौक शाहाबाद की 53वीं वार्षिक रामलीला की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन नगर के एक मैरिज लॉन में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संरक्षक श्री विनोद प्रकाश गुप्ता ने की। इसमें कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों और युवाओं की टीम ने भाग लिया।

उप कोषाध्यक्ष अम्बरीश द्विवेदी ने पिछले साल का आय–व्यय ब्योरा पेश किया, जिसमें बताया गया कि पिछले वर्ष का बजट मुनाफे में रहा। संरक्षक मंडल के सदस्यों विनोद प्रकाश गुप्ता, डॉ० मुरारी लाल गुप्ता, संजय मिश्रा (गोदी वाले) नलिन गुप्ता (डब्लू) शिवकुमार गुप्ता, रमाकांत मिश्रा और अभय सिंह वर्मा ने अपने संबोधन में मेला संस्थापक राजेश बाबू वर्मा और मेलाध्यक्ष चौधरी उमेश गुप्ता की तारीफ की। मेलाध्यक्ष चौधरी उमेश गुप्ता ने इस साल की रामलीला के लिए अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मथुरा की प्रसिद्ध श्री राधा रानी रासलीला संस्थान द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके अलावा, दर्शकों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था और रामलीला का बजट बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। मेला महामंत्री वासू वर्मा ने बताया कि पत्रिका प्रकाशन का काम चल रहा है और जल्द ही रामलीला की तैयारियां पूरे जोश के साथ शुरू की जाएंगी। बैठक में झांकी व्यवस्थापक राजेन्द्र रस्तोगी ने शोभायात्रा में निकलने वाली झांकियों को नया और आकर्षक रूप देने की बात कही।

अमानीगंज सहित कई जगहों पर सीवर लाइन के नाम पर खोद दिये बड़े-बड़े गड्ढे

अयोध्या।शहर के अमानीगंज कालोनी के अलावा शहर के सभी कालोनियों, मुहल्लों, मुख्य मार्गो पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है।यह कार्य जल निगम के अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराई जा रही है।जहां–जहां पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है वहां पर या तो कार्य अधूरा है या फिर उन जगहों पर बड़े–बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं।वही गड्ढे पाटने के नाम पर कुछ मिट्टी आदि संबंधित विभाग या कार्यदाई संस्था द्वारा डाल दी जा रही है।जो इस बारिश मे और मुसीबत बन रही है।इधर से गुजरने वाले राहगीरों तथा स्थानीय लोगों को इस मिट्टी के चलते परेशानियों का सामना करना पड है।शहर के हैदरगंज के साथ–साथ फतेहगंज ओवर ब्रिज से देवकाली तिराहा,शक्तिनगर कालोनी,अश्विनी पुरम कॉलोनी,रीडगंज तिराहा के अलावा कई प्रमुख मार्गो व मोहल्लो,कॉलोनियों मे इस गंभीर समस्या को देखा जा

सकता है।शहर के अमानीगंज गली में यह गंभीर समस्या बनी हुई है।यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी 5 माह पूर्व जल निगम द्वारा इस गली में पाइप बिछाने का कार्य हुआ था, कार्य पूरा भी नहीं हुआ कि फिर उस मार्ग को संबंधित विभाग द्वारा खुदवा कर फिर से पाइप डालकर वैसे छोड़ दिया गया।चलते उसे जगह पर आज भी बड़े–बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं।लोगों का मानना है कि यहां पर अस्पताल, स्कूल,मंदिर आदि होने के चलते काफी संख्या में मरीजों श्रद्धालुओं छात्राओं के साथ–साथ स्थानीय लोगों का आवाजाही लगा रहता है।स्थानीय लोगों ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने के बाद संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने इस मार्ग को वैसे ही छोड़ दिया।जिसके चलते बड़े–बड़े गड्ढे हो गए।वही इधर बारिश होने के चलते इन गधों में कई छात्र मरीज चोटिल हुए ।

खूंखार कुत्ते ने मासूम पर किया हमला, नाक नोंचकर भागा

भदोही, (संवाददाता)। बारिश में कुत्ते खूंखार हो गए हैं। रविवार की सुबह अभियां गोहरवा गांव में चार साल के मासूम अंकुश गौड़ पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और उसकी नाक का एक हिस्सा नोंचकर भाग गया। शोरगुल होने पर परिजन पहुंचे लेकिन तब तक कुत्ता भाग गया था। सुरियावां सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से सर्जरी के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। अभियां गोहरवा गांव निवासी अनिल गौड़ का चार साल का बेटा अंकुश रविवार की सुबह घर के दरवाजे के समीप बैठकर बिस्कुट खा रहा था। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता पहुंचा और बच्चे पर हमला कर दिया। यह देख आसपास के लोग शोर मचाते हुए बच्चे की तरफ भागे लेकिन तब तक कुत्ते ने बच्चे की नाक का एक हिस्सा काट लिया था। कुत्ते के हमले को देख सभी स्तब्ध रह गए। परिजन लहूलुहान हालत में बच्चे को लेकर सीएचसी पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर रेफर कर दिया गया। हालत चिंताजनक देखकर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। बच्चे पर कुत्ते के हमले से ग्रामीण सहम गए हैं। गांव के बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन चिंतित हैं। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रशासन से मांग की गई है। जिले में कुत्ते के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व भी 30 नवंबर 2022 को सुरियावां में छह साल के सागर पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। बचाने आई मां को भी काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

संक्षिप्त खबरें

मेजर ध्यानचन्द जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 से 31 अगस्त तक खेल का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर 25 अगस्त। क्रीड़ा अधिकारी ने अवगत कराया है कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी जिला खेल कार्यालय, जौनपुर के तत्वावधान में 29 अगस्त, 2025 को स्व0 मेजर ध्यानचन्द जी विश्व विख्यात हॉकी खिलाड़ी के जन्म दिवस को '''खेल दिवस''' के रूप में मनाया जायेगा। इस अवसर पर मेजर ध्यानचन्द को श्रद्धांजलि देने के साथ ही '''फिट इण्डिया''' की शपथ दिलाने के पश्चात 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों की 'जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता' का आयोजन प्रातः 9.30 बजे से इन्दिरा गांधी स्टेडियम सिद्दीकपुर के खेल मैदान पर किया जा रहा है। हॉकी प्रतियोगिता में कुल 08 टीमों को प्रविष्टि दी जायेगी। इच्छुक विद्यालय की टीमें अपनी प्रविष्टि जिला खेल कार्यालय, जौनपुर में उपस्थित होकर 26 से 28 अगस्त, 2025 तक कार्यालय अवधि में दर्ज करा सकती हैं। विद्यालय की टीमें अपनी प्रविष्टि विद्यालय के प्रधानाचार्य या खेल अध्यापक के माध्यम से करायेंगी। एक टीम में 16 खिलाड़ी एवं 01 प्रशिक्षक अथवा टीम मैनेजर होंगे, प्रतियोगिता में प्रविष्टि निःशुल्क है। प्रतियोगिता समाप्ति उपरान्त विजेता–उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जायेगा। 30 अगस्त 2025 को जूनियर बालक खो–खो की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता' का आयोजन किया जायेगा इसके अतिरिक्त भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फिट इण्डिया मिशन के अन्तर्गत ''सन्डे ऑन साइकिल'' का आयोजन 31 अगस्त 2025' को इन्दिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम से किया जायेगा जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों के साथ ही जन सामान्य को फिट रहने के साथ खनिज तेल की खपत कम करना है जिससे देश आत्मनिर्भर हो और प्रत्येक देशवासी स्वस्थ एवं बलशाली हो। उक्त साइकिल रेस में खिलाड़ियों के साथ ही नागरिकों से भी अपील है कि अपनी सहभागिता दें ताकि आयोजन को सफल व उद्देश्यपरक बनाया जा सके।

भागवत कथा से ही होता है जीवन का कल्याण – सम्पूर्णानंद महराज

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर स्थित नन्दीग्राम भरतकुंड में श्री भरत–हनुमान मिलन मंदिर दक्षिण मुखी प्राचीन गुफा में चल रही में सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को कलश पूजन के साथ हुआ। श्री मद् भागवत कथा के आयोजन महंत संत परमात्मा दास जी महाराज ने बताया कि कलश यात्रा प्राचीन भरत गुफा श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर नंदीग्राम भरतकुंड से भरत सरोवर होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की कलश यात्रा निकाली गई तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड मंदिर स्थल पर संपन्न हुआ। शुभारंभ अवसर पर कथा व्यास संपूर्णानंद जी महाराज जी महाराज ने कहा कि जो चीज कुसंग के प्रभाव में पल्बित, पुष्पित व फलित होती है उस पर कुसंग का दुष्प्रभाव सुनिश्चित है। कहा कि कुसंग के प्रभाव में आकर अच्छा से अच्छा इंसान भी दुर्जन हो जाता है इसलिए कुसंग से बचने का सदैव प्रयास करना चाहिए। इससे बचने का उपाय मात्र भागवत कथा श्रवण ही है। भागवत कथा श्रवण मात्र से ही जीव जन्म जन्मांतर तक शुद्ध हो जाता है। कथा ब्यास ने प्रथम दिवस की कथा में थाना गणेश पूजन व भागवत माहत्यम को विस्तार से बताया। कलश यात्रा में मुख्य यजमान अखिलेश पांडेय, कोमल सैनी,बंटी मोदनवाल, कमल सैनी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।

पीडीए समाज के महापुरुष मंडल मसीहा को समाजवादी नमन– राकेश मौर्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में अल्फस्टीन गंज स्थित जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित कर मंडल मसीहा, बीपी मंडल जी की 107 वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम उपस्थित सपाजनों ने मंडल आयोग के अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बीपी मंडल) जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि बीपी मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया. उन्होंने देश की तीन हजार सात सौ 43 अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान की और उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी सिफारिशें दी. बीपी मंडल जी की रिपोर्ट ने 90 के दशक के बाद भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी रिपोर्ट ने लागू होने के साथ देश में भूचाल–सा ला दिया. रिपोर्ट के पक्ष और विपक्ष में पूरा देश बंटा गया. हर तरफ आन्दोलन करते हुए छात्र नौजवान सड़क पर थे. राजनीतिक रूप से कोई राजनीतिक दल इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।आज उसी आंदोलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं, जातीय जनगणना कराकर पीडीए समाज को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और इस हिस्सेदारी को पाने के लिए 2027 में पीडीए कि सरकार बनाना जरूरी हो गया है। ऐसे मंडल मसीहा को समाजवादी नमन करते हैं।

लायंस क्लब जौनपुर गोमती ने मनाया तीज महोत्सव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर लायंस क्लब जौनपुर गोमती द्वारा नगर के एक प्रतिष्ठित होटल में अमर सुहाग के आगामी पर्व तीज के शुभ अवसर पर तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें क्लब की महिला सदस्यों द्वारा नृत्य, गीत – संगीत, मनोरंजक गेम्स आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत रीजन चेयरपर्सन प्रतिमा गुप्ता, क्लब की प्रथम महिला डा. रश्मि मौर्य, खुशबू गुप्ता ,नूपुर सिंह , डा सुलोचना सिंह ,डा.प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य महिला सदस्यों द्वारा शिव पार्वती के पूजन, देवी गीत व भजन – कीर्तन के साथ की गई। कार्यक्रम में महिला लायन सदस्यों ने अपने परिवार के महिला सदस्यों एवं बच्चों के साथ ग्रुप डांस, नृत्य प्रतियोगिता, क्विज एंड गेम्स, गीत – संगीत आदि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी नृत्य, गीत–संगीत व गेम्स आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतिभागी सभी महिलाओं को पुरस्कार व कार्यक्रम में उपस्थित सभी को आकर्षक गिफ्ट भेंट किए गए।

कार्यक्रम में नये सदस्य नंदिनी मौर्या,श्वेता साहू,सोनी जायसवाल द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया,रोशनी गुप्ता,श्रीजी साहू ने भजन गायन किया,रोली साहू,इंदु गुप्ता, डा प्रीती केसरवानी ने क्विज गेम्स में प्रतिभाग किया।कार्यक्रम में डा.सुलोचना सिंह ने तीज व्रत के महत्व पर प्रकाश डाला।अरुणा गुप्ता, अरुणा पाण्डेय, सीमा गुप्ता,संगीता साहू,निशा साहू,डा सरला गुप्ता, सोनिया जायसवाल, शशि जायसवाल, शोभा माहेश्वरी ,प्रज्ञा मिश्रा,प्रियंका गुप्ता,रीता केसरवानी,शकुन्तला बैंकर,शालिनी साहू,मीना साहू,निधि गुप्ता,शशि अग्रहरि,बिन्दु सिंह, बबिता साहू,श्वेता जायसवाल, सुनीता पाठक,सुनीता श्रीवास्तव, मंजू मिश्रा आदि सदस्य उपस्थित रहीं। क्लब की प्रथम महिला, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य महिला सदस्यों द्वारा कार्यक्रम संयोजक डा सुलोचना सिंह एवं डा प्रियंका श्रीवास्तव को माल्यार्पण कर,अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव खुशबू गुप्ता तथा धन्यवाद व आभार कोषाध्यक्ष नूपुर सिंह द्वारा ज्ञापित किया गया।

दिनभर छानी खाक पर नहीं मिला बाघ

सीतापुर, (संवाददाता)। महोली के नरनी गांव में बाघ की घेराबंदी के लिए वन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। खेतों में दो मचान बनाए जा रहे हैं। पिंजरा व 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम नवनिर्मित पीएचसी में बनाया गया है। दुधवा के 16 विशेषज्ञों की टीम ने नरनी में डेरा डाल दिया है। रविवार को दिनभर वन विभाग की टीम कॉम्बिंग करती रहीं। ड्रोन से भी नरनी के आस पास बाघ की तलाश की गई, लेकिन सुराग नहीं मिला। गांव में दहशत का माहौल है। खेतों की ओर जाना तो दूर लोग घर से निकलने में घबरा रहे हैं। बाघ ने महोली क्षेत्र के नरनी में शुक्रवार शाम बाघ के हमले में सौरभ उर्फ रवि दीक्षित (22) की मौत हो गई थी। वह घास काटने खेत गए थे। क्षत–विक्षत शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था। डीएफओ के मुताबिक सौरभ पर हमला करने वाला बाघ

कठिना नदी के किनारे–किनारे लखीमपुर खीरी से यहां पहुंचा था। रविवार को दुधवा से विशेषज्ञों की टीम भी नरनी पहुंच गई। दिनभर कॉम्बिग कर वन विभाग की टीम खेतों की खाक छानती रही। अब वन विभाग ने बाघ को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। नरनी के बाहर खेतों में दो मचान बनाए जा रहे हैं। टीमें इन पर बैठकर बाघ के मूवमेंट का इंतजार करेंगी। रविवार को पिंजरा लगा दिया गया। इसके साथ ही 10 ट्रैप कैमरे विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। दुधवा से आए विशेषज्ञ डॉ. दयाशंकर ने चार टीमों में शामिल 16 विशेषज्ञों के साथ नरनी की नवनिर्मित पीएचसी में डेरा डाला है। यहां कंट्रोल रूम बनाया गया है। टीमें 24 घंटे बाघ की मूवमेंट पर नजर रखेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार दोपहर बाद नरनी पहुंचे। बाघ के हमले में मारे गए सौरभ के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को तत्काल इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। बाघ को जल्द पकड़ा जाए, ताकि ग्रामीण सुरक्षित रह सकें। छह–छह घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करेंगी तीन टीमें : महोली वन क्षेत्राधिकारी कल्पेश्वर नाथ ने बताया कि महोली रेंज, हरगांव रेंज व सीतापुर रेंज की तीन टीमें गठित की गई हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।